(3) कॉफी बोर्ड को इस बात के निर्देश दे कि वह कॉफी की कुछ निश्चित मात्रा खरीदकर अपनी दुकानों की मार्फत उपलब्ध कराए । इन सुझावों की जांच गुणावगुण आधार पर की जाएगी ।

विदेशी व्यापार संतुलन

* 176. **श्री राघवजी :**

श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के लिए विदेशी व्यापार संतुलन के क्या अनुमान है ;

(ख) विदेशी व्यापार के कब तक भारत के पक्ष में होने की संभावना है ; और

(ग) सरकार इस संबंध मे क्या कदम उठाने जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1994 की अवधि (वह अवधि जिसके लिए व्यापार-आंकड़े उपलब्ध है) के दौरान भारत का व्यापार सन्तुलन घटा, 1394.90 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात अधिक हुआ । इस वर्ष के अन्त तक 2000—2500 मिलियन अमरीकी डालर का नकारात्मक व्यापार सन्तुलन हो सकता है ।

(ख) निर्यात तथा आयात भिन्न-भिन्न कारणो द्वारा शासित होते है और भारत का वार्षिक आयात आमतौर पर निर्यात की तुलना में अधिक होता है । इसमे 1972-73 और 1976-77 के वर्ष अपवाद-स्वरूप है जब आयात की तुलना मे निर्यात अधिक हुआ था योजना लक्ष्यों के अनुसार, व्यापार सन्तुलन मे घाटे को सतत रूप से कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे है ।

(ग) आयात इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उनसे स्वदेशी खपत और निर्यात उत्पादन के लिए अभिप्रेत माल के उत्पादन हेतु आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की जरुरतें पूरी करनी होती हैं । निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यापार के उदारीकरण हेतु बड़-बड़े उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं :– आयात से बड़े निर्यात में लोचशीलता, आयात लाइसेंसिग मे कमी करना, नीति एवं कार्यविधियों का सरलीकरण करके कार्यविधि संबंधी बाधाओ को समाप्त करना, और निर्यात की निषेधात्मक सूची में काट-छांट करना । निर्यात संवर्धन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह सरकार और व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रो के बीच सहयोग के प्रयास से किया जाता है । निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रो के परामर्श से सभी सभव उपाय किए जाते है । निर्यात संवर्धन में राज्यो को भी ईपीआईपी जैसी योजनाओं के जरिए अधिकाधिक रूप से शामिल किया जा रहा है ।

कोयले के भंडार की खोज

*177. **श्री अजीत जोगी :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर कोयले के भंडारो का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासो का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान व्यापक स्तर पर खनन करके कोयला खनन परियोजनाए शुरु करने के संबंध मे कोई व्यावहारिक अध्ययन किया गया है या कोई परियोजना रिपोर्ट तयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, बिलासपुर की भी पेन्ड्रा के पास बीजाडाड मे नई खदान खोलने की योजना है, यदि हा, तो उस पर कार्य कब आरंभ होगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1-1-1991 से 1-1-1994 की 3 वर्ष की अवधि के दौरान विस्थापित/मूल्याकित किए गए कोयले के अतिरिक्त भण्डारों का श्रेणीवार ब्यौरा, जोकि देश के विभिन्न अभिकरणो द्वारा किए गए क्षेत्रीय तथा विस्तृत अन्वेषणों पर आधारित हैं, नीचे दिया गया है :—

अतिरिक्त भंडार	मिलियन टन में	
प्रमाणित	(+) 9063.85	(विस्तृत ड्रिलिंग)
विनिर्दिष्ट	(+) 2056.97	(क्षेत्रीय ड्रिलिंग)
अनुमानित	(—) 6588.10	(विनिर्दिष्ट तथा प्रमाणित श्रेणियो में स्थानांतरित किए जाने के कारण)
निवल वृद्धि	4532.72	

(ख) से (घ) विस्तृत ड्रिलिंग से उपलब्ध भू-गर्भीय आंकड़ों के आधार पर 91 कोयला खनन परियोजनाएं तथा योजनाएं पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा निष्पादित की गई है । जैसाकि केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, इन परियोजनाओं/योजनाओं की कुल क्षमता 88.65 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है और इनकी अनुमानित लागत योजनाओं को निष्पादित किए जाने के समय चल रही कीमतों के स्तर पर लगभग 5760 करोड़ रुपए होने का हिसाब लगाया गया है ।

(ङ) मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिले के सेन्दुरगढ़ कोयला क्षेत्र में बिजाडांड के आसपास विस्तृत अन्वेषण किया गया है । इस क्षेत्र में नई खानों को खोला जाना, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित मुद्दों पर निर्भर करता है—जैसे तकनीकी-आर्थिक व्यवहायता, भूमि की उपलब्धता, वन तथा पर्यावरणीय अनुमोदन और वित्तीय संसाधन ।

Plan Allocation for Orissa

*178. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to enhance the allocation of funds to Orissa for implementing different poverty alleviation schemes;

(b) if so, the funds sanctioned for the purpose during the Eighth Five Year Plan period;

(c) the additional funds proposed to be allocated under various schemes during the remaining period of the Eighth Five Year Plan; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANGO): (a) to (d) The major rural poverty alleviation schemes being implemented in Orissa are (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP); (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY); and (iii) Employment Assurance Scheme (EAS). The IRDP provides self empolyment and the JRY and the EAS provide supplementary wage employment to the rural poor.

The central allocations for the poverty alleviation programmes are finalised each year. Under the IRDP and the JRY funds are allocated to the States on the basis of proportion of rural poor in the State to the total rural poor in the country. Hence the States which have a higher incidence of rural poverty receive proportionately larger allocations. 20 per cent of funds under the JRY are provided to 120 backward districts of the country where there is concentration of unemployment and underemployment : Of these 9 districts are in Orissa. For the EAS, which is a need based programme (launched on 2-10-93), no specific Statewise allocations are made. Initially some funds were released to the States for selected blocks, and subsequent instalments are released on receipt of proposals from the districts after they have spent 50% of the available funds. The scheme is being implemented in 1776 blocks of the country of which 143 blocks are in Orissa. The funds allocated towards these poverty alleviation schemes during the first three years of the Eigth Plan period are given in the table.

(Rs. in Lakhs)

Programme		1992-93	1993-94 (prov.)	1994-95 (prov.)
		Allocation	Allocation	Allocation
IRDP		3198.00	6826.00	6769.00
JRY	1st Stream	16036.90	19972.66	21984.43
	2nd Stream	—	7143.75	7143.75
EAS		—	5335 00*	7150 00*

*EAS. Funds Released: as no Statewise allocations are made under EAS.

For the remaining two years of the Eighth Plan the Statewise allocations, including that for Orissa will depend on the total budgetary support provided by the Central Government and the matching share to be provided by State Governments for the various poverty alleviation schemes. This shall be finalized at the commencement of each financial year.

Claims of Gujarat Government for Higher Rate of Royalty

*179. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lignite was clubbed with F & G grade of coal during